



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार, 7 सितम्बर, 2006/16 भाद्रपद, 1928

---

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला-171 002, 21 अगस्त, 2006

संख्या एच० पी० ई० आर० सी०/391.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) (ड) (ढ) (त) तथा (थ) संपठित धारा 39 की उप-धारा (2), के खण्ड (घ) धारा 40 के खण्ड (ग) के उप खण्ड

(ii), धारा 42 की उपधारा (2) तथा (4) तथा धारा 61 के खण्ड (छ) के अन्तर्गत शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

### विनियम

1. संक्षिप्त विस्तार नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रति-सहायिकी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार तथा प्रति-सहायिकी की चरण-बद्धता) विनियम, 2006 है।

(2) ये विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत के पारेषण/वितरण कारबार में लगे किसी भी व्यक्ति, आवद्ध ऊर्जा संयन्त्रों सहित सभी खुली पहुंच ग्राहकों को लागू होंगे।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) अभिप्रेत है;

(ख) “आयोग” से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) “अनुज्ञप्ति” से अधिनियम की धारा 14 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत पारेषित करने के लिए स्वीकृत की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसमें प्रदत्त समझी गई अनुज्ञप्ति भी आती है;

(घ) “अनुज्ञप्तिधारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई है या जिसे अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा गया है।

(2) शब्दों तथा पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, अर्थ वही होंगे जो कि उन के लिए अधिनियम में नियत किए गए हैं।

3. प्रति-सहायिकी अधिभार.—(1) धारा 42 की उप-धारा (2) के अधीन यथाउपबन्धित प्रति-सहायिकी अधिभार खुली पहुंच का विकल्प करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा संदेय होगा :

परन्तु यह कि प्रति-सहायिकी अधिभार ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अपने स्थान तक विद्युत के ले जाने के लिए आवद्ध उत्पादन संयन्त्र स्थापित किया हुआ है, देय नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जब विद्युत—

- (क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 43 क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन सक्षम सरकार की सहमति से उत्पादन कम्पनी द्वारा विक्रित की जाती है, या
- (ख) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा-27 के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त प्राधिकार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, प्रदाय की जाती है;

प्रति—सहायिकी अधिभार उस अवधि में जब तक उक्त सहमति अथवा प्राधिकार प्रभावी रहता है, देय नहीं होगा।

(2) प्रति—सहायिकी अधिभार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यपद्धति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति में विनिर्दिष्ट अधिभार सूत्र (फारमूला), जो नीचे दिया गया है, के अनुसार अवधारित किया जाएगा:—

$$S=T-[C(1+L/100)+D]$$

व्याख्या.—इस विनियम के प्रयोजनार्थ—

- (क) “S” से अधिभार अभिप्रेत है
- (ख) “T” से संबद्ध उपभोक्ता वर्ग द्वारा देय टैरिफ अभिप्रेत है;
- (ग) “C” से तरल इंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन तथा नवीनकरणीय ऊर्जा को छोड़कर, शिखरस्थ 5% मारजिन पर, ऊर्जा क्रय की वेटिड (weighted) औसत लागत अभिप्रेत है;
- (घ) “D” से चक्रण प्रभार अभिप्रेत है;
- (ङ) “L” से प्रतिशतता में व्यक्त वोल्टेज स्तर पर लागू प्रणाली क्षति अभिप्रेत है;

4. प्रति—सहायिकी अधिभार का घटाव तथा समापन.—(1) प्रति—सहायिकी अधिभार की चरणबद्धता पांच वर्ष की अवधि में होगी तथा 5 वर्ष की अवधि के अन्त में प्रति—सहायिकी अधिभार आधार वर्ष में इसके प्रारम्भिक स्तर के 20 प्रतिशत के आदर्शमूलक (normative) स्तर पर होगा।

(2) प्रति-सहायिकी अधिभार की समाप्ति हेतु आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2006 होगा और चरणबद्धता खुली पहुंच ग्राहकों के लिए प्रति-सहायिकी अधिभार के सन्दर्भ में होगी और प्रथम वर्ष में 100

वर्ष	चरणबद्धता योजना
वित्तीय वर्ष 2006	100 प्रतिशत
वित्तीय वर्ष 2007	84 प्रतिशत
वित्तीय वर्ष 2008	68 प्रतिशत
वित्तीय वर्ष 2009	52 प्रतिशत
वित्तीय वर्ष 2010	36 प्रतिशत
वित्तीय वर्ष 2011	20 प्रतिशत

5. प्रति-सहायिकी अधिभार के संदाय और उपयोग की रीति.—(1) प्रति-सहायिकी अधिभार, जो एक प्रतिकारक प्रभार है, उस क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी को जहां उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय की जाती है, संदेय है; का उपयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में करेंट लेवल प्रति-सहायिकी की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(2) प्रति-सहायिकी अधिभार की वसूली, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण उपयोगिता, जिसकी सुविधाओं का उपयोग उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्राप्ति के लिए किया जाता है, द्वारा मासिक आधार पर की जायेगी। इन सभी मामलों में उपभोक्ता से वसूल की गई राशि उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त की जानी चाहिए, जिसके क्षेत्र में उपभोक्ता संस्थित है और यदि एक ही क्षेत्र में दो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय कर रहे हों, तो वसूल की गई राशि उस अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त की जानी होगी जिस से उपभोक्ता विद्युत प्रदाय की सुविधा ले रहा था।

6. अतिरिक्त अधिभार.—(1) खुली पहुंच उपभोक्ता, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदाय करने की बाध्यता से उद्भूत नियत लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अधिभार, संदाय करेगा।

(2) अतिरिक्त अधिभार, किसी उपभोक्ता, जिसमें अपने स्वयं के उपयोग हेतु आवद्ध संयन्त्र लगाने वाला सम्मिलित उपभोक्ता भी है, द्वारा संदेय होगा।

(3) अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (4) के अधीन विद्युत प्रदाय की बाध्यता के लिए अतिरिक्त अधिभार केवल तभी संदत्त होगा जब यह निश्चायक रूप से प्रमाणित हो जाता है कि

अनुज्ञापिधारी की बाध्यता विद्यान ऊर्जा क्रय की प्रतिबद्धताओं के अनुसार उत्कूलित हो गई है अथवा अनुबन्ध के परिणामतः उस द्वारा नियत लागत का भार वहन करना तथा बाध्यता पूरा करना अनिवार्य हो गया है। नैटवर्क आस्तियों से सम्बन्धित नियत लागत चक्रण प्रभार के रूप में वसूल की जायेगी।

(4) प्रत्येक वितरण अनुज्ञापिधारी प्रदाय करने की बाध्यताएं पूरा करने के लिए उस द्वारा उपगत नियत लागत का ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत करेगा;

(5) आयोग, अतिरिक्त अधिभार अवधारण करते हुए, वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए नियत लागत के ब्यौरे की संविक्षा करेगा और साधारण जनता तथा प्रभावित पक्षों से आपत्तियां आमन्त्रित करेगा और उन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

(6) अतिरिक्त अधिभार अवधारण वार्षिक आधार पर होगा और इसे एकमुश्त या मासिक आधार पर वसूल किया जा सकेगा।

**7. प्रसारण एवं वितरण हानि में खुली पहुंच ग्राहकों द्वारा भागीदारी.**—(1) खुली पहुंच उपभोक्ता, आयोग द्वारा अवधारित प्रणाली में विद्यमान पारेषण एवं वितरण हानि को वहन करेगा और इन प्रभारों का केवल तकनीकी हानियों के लिए विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर वस्तु-विनियम के रूप में (in kind) संदाय करेगा—

(क) जहां खुली पहुंच उपभोक्ता के अन्तःक्षेपण बिन्दु तथा आहरण बिन्दु भिन्न-2 वोल्टेज स्तरों पर हैं, प्रभारों का वस्तु-विनियम के रूप में (in kind) संदाय अन्तःक्षेपण बिन्दु पर प्रचलित तकनीकी हानि का 50 प्रतिशत तथा आहरण बिन्दु पर प्रचलित तकनीकी हानि का 50 प्रतिशत होगा;

(ख) जहां खुली पहुंच उपभोक्ता के अन्तःक्षेपण बिन्दु तथा आहरण बिन्दु उसी वोल्टेज स्तर पर हो, प्रभारों का वस्तु-विनियम के रूप में (in kind) संदाय उस वोल्टेज पर प्रचलित हानि पर होगा।

**8. सामान्य शर्तें.**—(1) इन विनियमों में कुछ भी, आयोग को ऐसे आदेश जारी करने की शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा, जो न्यायदान हेतु आवश्यक हो।

(2) इन विनियमों में कुछ भी, आयोग को ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन से भिन्न हों यदि आयोग को किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु न्याय पूर्ण एवं उचित लगे।

(3) इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने को नहीं रोक सकता जो इन विनियमों में इन से भिन्न हों, यदि आयोग किसी अपरिहार्य घटना के दृष्टिगत ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु न्यायपूर्ण या उचित समझे।

(4) इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त व विवक्षित रूप से, किसी विषय के निर्वहन या अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से आयोग को नहीं रोक सकेगा, जिनके लिए पृथक् से विनियम नहीं बनाए गए हैं तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों एवं कार्यों पर ऐसे तरीके से कार्यवाही कर सकेगा जैसा वह न्यायपूर्ण एवं उचित समझे।

9. संशोधन की शक्ति.—आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को परिवर्धित, परिवर्तित, बदल, उपांतरित या संशोधित कर सकेगा।

10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां.—यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कठिनाई उत्पन्न हो, तो आयोग को, या तो स्वप्रेरणा से या इसे आवेदन किए जाने पर, ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से, सामान्य या विशेष आदेश जारी कर अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे कार्य अथवा उत्तरदायित्व निभाने की बावत निदेशित करने के अधिकार होंगे जो अधिनियम से असंगत न हो और आयोग के मतानुसार कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक या उपयुक्त हों।

11. आदेशों तथा कार्यपद्धति सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी करना.—अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप आयोग, समय-समय पर, ऐसे आदेशों तथा कार्यपद्धति सम्बन्धी दिशा-निर्देश जो इन विनियमों के क्रियान्वयन एवं प्रक्रिया के अनुसरण तथा तत्सम्बन्धित आनुषंगिक या सहायक विषयों के सम्बन्ध में हैं, जारी कर सकेगा।

12. निर्वचन.—इन विनियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में उद्भूत सभी विवाद्यक आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे और ऐसे विवाद्यकों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

आज्ञा से,

हस्ताक्षरित /—

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग।

[Authoritative English text of this department notification No. HPERC/391, dated 21-8-2006 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

*Shimla-171 002, the 21st August, 2006*

**No. HPERC/ 391.**—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the powers vested in it under clauses (i), (j), (k), (l), (m), (n), (p) and (q) of sub-section (2) of section 181, read with clause (d) of sub-section (2) of section 39, sub clause (ii) of clause (c) of section 40, sub-sections (2) and (4) of section 42, and clause (g) of section 61 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, and after previous publication, hereby makes the following regulations, namely:—

### REGULATIONS

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) Regulations, 2006.

(2) These regulations shall be applicable to any person engaged in the business of transmission/distribution of electricity, and open access customers including captive power plants in the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) “Commission” means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(c) “licence” means a licence granted under section 14 of the Act and shall include the deemed licensee for the purpose; and

(d) “licensee” means a person who is granted a license under section 14 of the Act or is a deemed licensee under the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meanings as are assigned to them in the Act.

**3. Cross subsidy surcharge.**—(1) The cross subsidy surcharge as provided under sub-section (2) of section 42 of the Act shall be payable by the consumers availing Open Access:

Provided that no cross subsidy surcharge shall be payable by a person who has established a captive generating plant for carrying the electricity to the destination of his own use:

Provided further that no cross subsidy surcharge on the electricity being—

(a) sold by the generating companies, with the consent of the competent Government under clause (c) of sub-section (1) of section 43 A of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948); or

(b) supplied by the distribution licensee, on the authorization by the State Government under section 27 of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910);

shall be payable during the period such consent or authorization remains in force.

(2) The cross subsidy surcharge shall be determined by the Commission on a methodology and surcharge formula specified in the National Tariff Policy, which is given as under:—

$$S = T - [C (1+L/100) + D]$$

**Explanation.**—For the purpose of this regulation.—

(a) “S” is the Surcharge.

(b) “T” means Tariff payable by the relevant category of consumers.

(c) “C” is the Weighted average cost of power purchase of top 5% at the margin excluding liquid fuel based generation and renewable power.

(d) “D” is the Wheeling Charge

(e) “L” is the system losses for the applicable voltage level, expressed as a percentage.

**4. Reduction and Elimination of cross-subsidy surcharge.**—(1) The phasing of the cross subsidy surcharge shall be within a period of five years, and the cross subsidy surcharge at the end of 5 years shall be at a normative level of 20% of its opening level in the base year.

(2) The base year for starting the elimination of cross subsidy surcharge shall be the financial year 2006 and the phasing will be in terms of percentage of the cross subsidy surcharge to



be made applicable to the Open Access Customer—starting from 100% in the first year to 20% in the sixth year as detailed in the Table hereunder:—

Year	Phasing Plan
FY 06	100%
FY 07	84%
FY 08	68%
FY 09	52%
FY 10	36%
FY 11	20%

**5. Manner and utilization of payment of Cross subsidy surcharge.**—(1) The Cross subsidy surcharge which is a compensatory charge payable to the distribution licensee of the area where the electricity is delivered to the consumer, shall be utilised to meet the requirements of current level of cross subsidy within the area of supply of the distribution licensee.

(2) The Cross subsidy surcharge shall be collected on a monthly basis either by the distribution licensee or the transmission licensee, or the STU, depending on whose facilities are used by the consumer for availing electricity supplies. In all cases, the amount collected from a consumer shall be paid to the distribution licensee in whose area the consumer is located and in case of two licensees supplying in the same area, the licensee from whom the consumer was availing supply shall be paid the amount collected.

**6. Additional surcharge.**—(1) An open access consumer shall also pay to the distribution licensee an additional surcharge to meet the fixed cost of such distribution licensee arising out of his obligation to supply as provided under sub-section (4) of section 42 of the Act.

(2) Additional surcharge will be payable by any consumer including any consumer who puts up a captive plant for his own use.

(3) The additional surcharge for obligation to supply as per sub-section 4 of section 42 of the Act shall become applicable only if it is conclusively demonstrated that the obligation of a licensee, in terms of existing power purchase commitments, has been and continues to be stranded, or there is an unavoidable obligation and incidence to bear fixed costs consequent to such a contract. The fixed costs related to network assets would be recovered through wheeling charges.

(4) Each distribution licensee shall submit to the Commission, details of fixed costs, which the licensee is incurring towards his obligation to supply.

(5) In determining the additional surcharge, the Commission shall scrutinize the details of fixed costs submitted by the distribution licensee and invite and consider objections, if any, from the public and affected parties.

(6) The additional surcharge shall be determined on annual basis and it can be collected either as one time payment or on monthly basis.

**7. Transmission & distribution loss sharing by Open access customers.**—(1) The Open access consumer shall, as determined by the Commission, bear the transmission and distribution losses existing in the system and pay for these charges in kind for only technical losses at various voltage levels—

- (a) where the point of injection and point of drawl by the open access consumer, are at different voltage levels the charges payable in kind will be 50% of the technical loss prevalent at the injection point and 50% of the technical loss prevalent at drawl point.
- (b) where the point of injection and point of drawl by the open access consumer, are at the same voltage levels the charges payable in kind will be the prevalent technical losses at that voltage.

**8. General conditions.**—(1) Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the powers of the Commission to issue such orders as may be necessary to meet the ends of justice.

(2) Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or a class of matters, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

(3) Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the force majeure events, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

(4) Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, restrict the Commission from dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner, as it considers just and appropriate.

**9. Power to Amend.**—The Commission may, at any time add, vary alter, modify or amend any provisions of these regulations.

**10. Power to remove difficulties.**—In case any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, either *suo motu* or on an application made to it, do or undertake to do things, or by general or special order direct the licensee to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

**11. Issue of orders and directions.**—Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and procedure to be followed for such implementation and matter incidental or ancillary thereto.

**12. Interpretation.**—All issues arising in relating to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

By order,

Sd/-

Secretary,

*Himachal Pradesh State Electricity Regulatory Commission.*

